SHRIMATI MAIMOONA SULTAN: Sir, I would like to know whether M/s. Abbotts are producing animal drugs and whether the formulation capacities of this Company are mostly in respect of non-essential items and on the 18th August 1982, a specific condition was laid down that this Company would achieve the ratio of 1:10 within two years, that is, before 1985, and, if so, I would like to know whether this parameter has been achieved. Failing that, I would like to know whether this Company has exported the entire production and, if so, the name of the country and the names of the formulations. If neither has been done, I would like to know whether the licence has been cancelled or not.

SHRI VEERENDRA PATIL: Sir, this Company, which was started....

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Reeyeled newsprint produced by Tirupati Newsprint Limited

*368. DR. LOKESH CHANDRA:
SHRIMATI MAIMOONA SULTAN:

Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the quantum of recycled newsprint produced by the Tirupati Newsprint Limited, Champa (Madhya Pradesh) during the year 1984-85; and

(b) whether licences for any more newsprint recycling plants have been issued in order to minimise the need for import of newsprint?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) The newsprint project of M/s. Tirupati News print Limited has not been set up yet.

(b) Besides the existing installed capacity of 2.80 lakh tonnes for manufacture of newsprint, an additional capacity of 7,75,500 tonnes has been approved by way of Industrial Licences/Letters of Intent, inclusive of the capacity of 79,000 tonnes granted to M/s. Tirupati Newsprint Ltd. Of this, a capacity of 6.96 lakh tonnes is based on de-inking/recycling of waste newspaper.

Allotment of Kerosene to various States

*369. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of PETROLEUM be pleased to state:

(a) the State-wise allotted quota of kerosene for the year 1985-86, month-wise;

(b) the State-wise demand for kerosene during the same period;

(c) the actual supply so far made by the Centre to the States, State-wise and month-wise;

(d) the names of the States where demand for kerosene has incrased and what are the reasons thereof; and

(e) what steps Government have taken to meet the situation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM (SHRI NAWAL KISHORE SHARMA): (a) to (c). The kerosene requirement of States and Union Territories is determined by allowing 5 per cent growth over the allocation made for the corresponding period of the previous year.

A statement giving allocations and supplies of kerosene made to various States/Union Territories from April to July, 1985 is laid on the Table of the Sabha. [*See* Appendix CXXXV, Annexure No. 50].

(d) and (e) Apart from temporary factors like flood, drought, cyclone, shortage of alternative fuels etc. with increasing population, the demand of

kerosene is ring all over the country. Increased regular allocations, besides *ad-hoc* releases, are made in this context.

उद्योगों की स्थापना

*370. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में मध्यम और बड़े पैमाने के कुल कितने उद्योग स्थापित किये गये; उनमें से कितनों को लाइसेंस प्रदान किये गये हैं तथा उनमें से कितने स्वतन्त्र रूप से और कितने सरकारी सहायता से स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) क्या बिहार में उद्योग बन्द होते जा रहे हैं; यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में इस राज्य को सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन स्वीकृत किये गये आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा पंजीकृत योजनाओं की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरणों की सं०
1983	1055(211)	1075(95)	2024
1984	1064(173)	905(73)	1854

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित हैं जिनमें लघु उद्योग विकास निगम और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित हैं । ये आशयपत्र, औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिये विकास संबंधी केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान वितरित की गई राज-सहायता की राशि निम्नप्रकार है :—

	(करोड़ रुपये)
1983-84	53.20
1984-85	85.00

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में जून, 1984 के अन्त में बड़े क्षेत्र में 13 रुग्ण एकक और दिसम्बर, 1983 के अन्त में 3540 रुग्ण एकक थे । रुग्ण औद्योगिक एककों, जो आर्थिक दृष्टि से जीव्य हैं, की पुनः स्थापना पर सरकार द्वारा अक्तूबर, 1981 को जारी किए गए रुग्ण उद्योगों संबंधी नीति विषयक मार्ग-दर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सहायता करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अलग-अलग गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है । यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ?

इन नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रमुख विशेषताएं राज्य सभा में 15-7-1982 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 700 के उत्तर में दी जा चुकी है ।